Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 148-151

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका

रेणु कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

जाति ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें सदस्यता जन्म से तय की जाती है। प्रमुख तौर पर जातियों का विभाजन सवर्ण जातियों, पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में किया जाता है। यह प्रणाली भारतीय ईसाई तथा भारतीय मुसलमान वर्ग में भी राजनीतिक प्राथमिकताएँ होती है। इन सभी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भारत में आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था विकसित की गई। भारत में जातियाँ राजनीतिक प्रणाली के साथ-साथ न्यायिक सहायता तक पहुँच को भी नियंत्रित कर सकती है। प्रत्येक जाति अपने आवश्यकताओं अनुसार स्थानीय माँगों के आधार पर राजनीति को प्रभावित करती है तथा उसमें प्रतिनिधित्व की मांग भी करती है। आमतौर पर भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व निम्न जाति की महिलाओं से न आकर उच्च जाति की महिलाओं से आता है। इस विभेद को मिटाने हेतु आरक्षण व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू है। राजनीति पर जाति का प्रभाव समय के साथ उसका अभिन्न अंग बनता जा रहा है। राजनीतिक दल जनता को प्रभावित करने के लिए जातिवाद का सहारा लेते है। पिछड़ी जाति तथा दलित वर्ग के उत्थान के लिए जातिवाद को राजनीति का प्रमुख अंग बना दिया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था जहाँ पिछड़े हुए वर्गों को राजनीतिक भूमिका में प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था पर आधारित थी वही अब राजनीतिक दलों द्वारा संविधान की अप्राकृतिक व्याख्या कर जातियों को लुभाकर राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है तथा इसका वास्तविक उद्देश्य केवल जातियों को सन्तुष्ट करने पर ही रह गया है जिसके कारण जातियों के राजनीतिक विकास की अवधारणा धूमिल हो गयी है।

संकेताक्षर—*संसदीय शासन व्यवस्था, क्षेत्रीयतावाद, निर्वाचन राजनीति, जाति व्यवस्था*

प्रस्तावना

भारत में वोट बैंक की राजनीति का प्रमुख आधार जाति तथा वर्ग हैं। जाति के पदानुक्रम ओर राजनीति में इसकी भूमिका और सत्ता तक पहुंचने जाति के आधार पर संरक्षक ग्राहक सम्बन्धों का समाज बनाया है। इस व्यवस्था ने अन्ततः वोट बैंक की प्रथा को जन्म दिया जहाँ मतदाता केवल उन्हीं की जाति के उम्मीदवार को समर्थन करते है तथा जीते हुए प्रतिनिधि से लाभ की अपेक्षा भी जाति के आधार पर करते है। राजनीति में जाति की गतिशील शक्ति में लिंग आधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उदाहरण वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में योगदान से देखा जा सकता है। किन्तु यह लिंग आधारित महिलाओं का प्रभाव भी जातीय व्यवस्था से अलग नहीं है। भारतीय राजनीति में अगड़ी जातियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अन्य सभी पिछड़ी जातियों की महिलाओं से अधिक है। विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जातियों की महिलाओं का अधिक आर्थिक ओर राजनीतिक प्रतिनिधित्व निम्न जातियों की महिलाओं हेतु एक अभिशाप है जाति की राजनीति का संबंध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित से भी संबंधित है। भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली, सामाजिक प्रतिबंध तथा सकारात्मक कार्यवाही का एक आधार है।

भारतीय राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गयी है। जाति चेतना एवं जातिगत संगठनों के उदय ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लागू होने के बाद सभी वर्गों की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है तथा ये वर्ग बहुत मजबूत ताकत बनकर उभरे है।

स्वाधीनता के पश्चात् तथा संविधानिक क्रियाओं के प्रादुर्भाव से यह सम्भावना व्यक्त की जाने लगी कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात् जातिवाद समाप्त हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि जातिवाद ने न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी प्रवेश कर अग्र रूप धारण कर लिया है। स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय राजनीति में जातिवाद राजनीतिक अलगाव का प्रमुख आधार बन गया है। राजनीति में प्रमुख सभी मुद्दा बनकर रह गया है। केन्द्र ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय राजनीति भी जातिवाद से प्रभावित है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत में जातिवाद नामक मानसिकता बहुत पुरानी है। जो समाज को जाति के आधार पर बांटने का कार्य निरन्तर करती रही है। संविधान निर्माण के पश्चात् इस व्यवस्था का अन्त करने हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों पर अधिक जोर दिये जाने का प्रयास किया गया, कभी किन्हीं राजनेताओं के द्वारा तो कभी सुधार प्रस्ताव के द्वारा जातिवाद नामक मानसिकता को सुधारने का प्रयास किया जाता रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में जातिवाद नामक भंयकर बीमारी बनी हुई है। जातिवाद में प्रमुख तौर पर अति-पिछड़े तथा दलित वर्ग के लोगों का शोषण निरन्तर जारी है। भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण धरा पर जाति प्रथा किसी ने किसी रूप से राजनीति में अपना नकारात्मक प्रभाव को बनाकर रखा है। भारत की तरह ही अन्य देशों में भी जाति विशेष के संगठन ही राजनीति में अधिक प्रभावी है। भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति आधारित रहा है। भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति आधारित रहा है। ओर राजनीति इसी सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए यह कहाँ जाता है कि सामाजिक व्यवस्था राजनीति का स्वरूप निर्धारण करती है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में जातिवाद की भूमिका राजनीति में अधिक प्रभावी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता उन संस्थानों के खिलाफ थे जो जाति आधारित राजनीति में संलग्न थे।

राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ अधिक रूप ले रहा है लेकिन जाति व्यवस्था का यह रूप परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होता रहता है। भारत में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। कार्यपालिका के प्रमुख केन्द्र मंत्रीमण्डल के निर्माण में भी जातिगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिल रहा है। जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की परिकल्पना में कमी देखी जा सकती है। वर्तमान राजनीति में जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास अन्ततः राजनीति में मतदाताओं को जाति आधारित चुनाव करने पर विवश कर रहा है। उम्मीदवार मतदाताओं की भावनाओं को जाति से जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाते है। तथा उसी के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते है। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में भी जातिगत आधारित आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को प्रशासन में भागीदार बनाया जा सके।

जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय जो लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुँच गए है वे राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए है। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा ना ले फिर भी ये अपनी जातिवाद आधारित पृष्ठ भूमि को भूलते नहीं है। वे अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैरवी करते रहते है। इसी भावना के कारण कभी-कभी वे राजनीति में योग्यता आधारित व्यवस्था को दरकिनार कर जातिगत आधारित राजनीति को ही तवज्जो देते है। जिससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलगाव का बीज बोते है। राजनीति में जातीय आधारित सरकार का प्रमुख कारण भी जातिवाद ही है। इसका उदाहरण है राजनीति में उम्मीदवारों के टिकट वितरण में जातिगत आधारित आरक्षण की व्यवस्था है। राजनीति में हिंसा का प्रमुख कारण जातीय संघर्ष का प्रवेश है। जाति एक उपलाभ पदावली बन गयी है। जाति व्यवस्था अलग-अलग जातियों को आर्थिक व राजनीतिक ताकत बाँटती है। जिसके आधार पर जातिवाद की सोच को बढ़ावा मिलता है। भारत में राजनीति एक प्रमुख आधार है जो जातिवाद का स्रोत बना है। जाति ऐसे समुह का समुच्चय है जो किसी न किसी कारण से जन्म आधारित विभेदनाओं से अभिप्रेरित है। प्रत्येक जाति की सामाजिक और राजनीतिक पूर्वधारणा जन्म से ही निर्धारित होती है। निम्न जाति के संगठन निम्न जाति के ही उम्मीदवार या नेता को चुनते है। तथा उनसे जाति आधारित लाभ ही लेने का प्रयास करते है। जाति में इसी पूर्वधारणाओं के कारण ही भारतीय राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। जो जाति प्राचीन समय से अपने को उच्च जाति के दर्जे में मानती है।

वह केवल उच्च जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और अपने आर्थिक व सामाजिक लाभों की अपेक्षा करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा होती है कि उम्मीदवारी जो राजनीति में बदलाव के आधार पर विकास कार्यों को बढ़ावा दे उसी उम्मीदवारी का जनता साथ दे किन्तु भारतीय सामाजिक बुराई जातिवाद या जाति आधारित समाज में केवल जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। जो की पूर्णतः लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध है। इसके कारण भारत में आधुनिक सोच जो सभी नागरिकों को समान अवसर की अवधारणा व समाज के सभी क्षेत्रों में दक्षता आधारित सोच का परिघटन हो रहा है।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियानों के द्वारा यह जागरूकता मतदाताओं में दी जाती है कि वे जातीवाद से ऊपर उठकर अपने मतों का प्रयोग करे तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन करे ना की अपनी जाति को देखकर मत का प्रयोग करें। निर्वाचन आयोग यह भी प्रयास करता है की उम्मीदवार जाति आधारित चुनाव प्रचार से दूर रहें। भारत में जाति आधारित चुनाव एक आम समस्या है जिसका निदान मतदाताओं में जातिवाद को लेकर जागरूकता तथा जातिवाद के कुप्रभावों की शिक्षा देकर किया जा सकता है।

जाति और राजनीति में संबंध

भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही जाति महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। जातिगत मतदान भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग सामाजिक बुराई के आधार पर उभरा है। वयस्क मताधिकार लागू होने के पश्चात् भी जाति एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। भारत में जाति और राजनीति में संबंध बहुत प्रकार से देखा जा सकता है। जिसके आधार निम्न है—

1. भारत में सामाजिक व्यवस्था का आधार जाति है और राजनीति सामाजिक संबंधों से ही अभिप्रेरित होती है। और राजनीति का स्वरूप निर्धारित करती है।
2. राजनीति संगठनों के सहयोग से कार्य करती है। और यह संगठन भारत में जाति के आधार पर अपना वर्चस्व रखते है जो परोक्ष-अपरोक्ष रूप से भारतीय राजनीति को जातिवाद का एक प्रमुख आधार प्रदान करते है।
3. सामान्यतः लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक संरचनाओं के आधार पर चलती है। तथा यह सामाजिक संरचनाएँ समाज में व्याप्त मूल्यों से बनती है। किन्तु भारत में सामाजिक मूल्यों में जाति व्याप्त है। जिससे यह जातिगत आधारित राजनीति को प्रेरित करती है।
4. मूल तौर पर राजनीतिक दल राजनीतिक सिद्धान्तों के दिखावे के तौर पर जाति का विरोध करते है। किन्तु चुनावों में परोक्ष व अपरोक्ष रूप से जाति आधारित वोट बैंक को बढ़ावा देते है।
5. भारत में किसी भी राजनीतिक दल का प्रभुत्व इससे निश्चित किया जाता है। की वह राजनीतिक दल कितनी जातियों के कितनी जनसंख्या को जातिगत आधारित मतदान हेतु प्रभावित करते है। साधारण शब्दों में जो दल जितनी बड़ी जाति जनसंख्या को अपने दल के पक्ष में वोट रखता है। वह उतना ही बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है।
6. भारत में जातियाँ सरकार बनाने में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब कोई जाति विशेष किसी राजनीतिक दल विशेष को वोट करती है। तो यह अवश्य ही अपेक्षा करती है की सरकार में उनके जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व अधिक मिलेगा।
7. भारत में राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख आधार भी जातिगत व्यवस्था से ही प्रभावित है क्योंकि समाज में विभिन्न-विभिन्न जातियों के लोग सामाजिक समन्वय को छोड़कर राजनीतिक दलों के जातिगत आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रलोभनों में आकर अपने मतों का प्रयोग करते है। जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है।
8. भारत की कार्यपालिका का प्रमुख आधार मंत्रीमण्डल में प्रतिनिधित्व भी जाति के वोट बैंक के महत्व के आधार पर दिया जाता है।
9. भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा कानून या नियमों का निर्माण या संशोधनों को भी यह देखकर किया जाता है की इन बदलावों से कौनसी जाति पर क्या प्रभाव होगा।
10. राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों का चुनाव योग्यता व सेवा तत्वों को दर-किनार कर मुख्यतः जातीय मापदण्डों से ही किया जाता है।

चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका

जातिगत चेतना व जातिगत संगठनों के उदय ने भारतीय राजनीति व्यवस्था को बदल दिया है। जिसके कारण अब भारतीय राजनीति का जाति एक अभिन्न अंग बन गयी है।

भारत की चुनावी राजनीति में जाति को दो प्रकार से देखा जा सकता है प्रथम यह की उम्मीदवारों को जाति के आधार पर चुना जा सकता है। या फिर कहा जा सकता है की राजनीतिक दल टिकटों का बँटवारा उम्मीदवार की जाति देखकर करते है। दूसरा पहलू यह है की भारत में राजनीतिक दलों का बनना मुख्य तौर पर जातियों का समर्थन ही होता है। उदाहरण के तौर पर बहुजन समाज पार्टी तथा आजाद मौर्चा पार्टी का आधार दलित वर्ग का समर्थन ही था जिसके अलावा कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन भी था।

पॉल ब्रास ने इसे "जातियों का महागठबंधन" कहा था इन रणनीतियों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिये जातियों के आधार पर टिकट तय करती है। यहां तक की वोट देने वाले भी जाति के आधार पर ही वोट डालते है।

इस संदर्भ में रजनी कोठारी का कहना है कि 'राजनीति के जातिवाद' जाति के राजनीतिकरण से ना कम है या ज्यादा है। अन्य शब्दों में, राजनीति पर जाति का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है बल्कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है। जाति भारत में सामाजिक एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक संस्था के रूप में यह वृहत मजबूती के साथ खड़ी है और आधुनिकरण के युग में भी जाति अभी विद्यमान है। यद्यपि जाति के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है फिर भी यह राजनीति एवं दलों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गयी है एवं कोई भी राजनीतिक दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकता।

जाति भारत में अपने शासन को उचित ठहराने का एक उपकरण बन गई। इस से लोगों के बीच जातिगत झगड़े शुरू हो गये। सामाजिक चेतना में जाति भी मंथन करने लगी। अतः भारतीय समाज में जाति का विकास होने लगा आधुनिक संविधान ने 1976 (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम) में को समाप्त कर दिया, सीटों का आरक्षण किया जिसके परिणामस्वरूप जाति का और भी अधिक ठोसकरण हुआ है। भारत में जाति-पाती कभी मिटी नहीं। कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा अपनाई गई राजनीति लामबंदी की नीति के परिणामस्वरूप कई निचली जातियों को भी पार्टी में शामिल किया गया।

निष्कर्ष

राजनीति और जाति एक दूसरे को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक बनकर उभरे है। राजनीतिक दलों के निर्माण से लेकर उनके विघटन को कारकों में जाति का कारण अग्रिम भूमिका में है। खासकर उत्तर-भारत के प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर-प्रदेश, बिहार, राजस्थान राज्यों में जातिगत राजनीति की भागीदारी प्रमुख है। आरक्षण से पिछड़े समाज में कई नेताओं की राजनीतिक भागीदारी में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। जिसमें भारतीय राजनीति में लाभकारी परिवर्तन को तो बढ़ावा दिया है किन्तु साथ ही साथ समाज में विभिन्न जातियों के मध्य हिंसा की प्रवृति को भी बढ़ावा दिया है। भारतीय राजनीतिक दल एवं नेता अब जाति को उनके सफल रणनीति के तौर पर आजमाया है और वे सफल भी हुए है। अतः यह कहाँ जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद भी राजनीति में जाति के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, दीपांकर, इंटेरोगेटिंग कास्ट, नई दिल्ली, पेंग्यूविन, 2000
2. ऑमवेल, गेल, काशीराम एण्ड बहुजन समाज पार्टी, के.एल. शर्मा (सं.) में, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1994
3. मेहता, प्रताप भानु, द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, नई दिल्ली, पेंग्यूविज, 2003
4. कोठारी, रजनी, कास्ट इन इंडियन पोलिटिक्स, ओरियंट हैदराबाद, लोंगमेन, 1970
5. शाह, घनश्याम (सं.), कास्ट एण्ड डैमोक्रेटिक पोलिटिक्स इन इंडिया, न्यू डेल्ही परमानेंट ब्लैक, 2004
6. शाह, ए.एस., कास्ट इन द 21 सेन्चुरी : फोर्म सिस्टम ऐलिपेंटस, ई.पी. डब्ल्यू, 42(44), 2007, पृ.सं. 109-116
7. पॉल.आर. ब्रास, कास्ट, फेक्शन एन्ड पार्टी इन इण्डियन पोलिटिक्स, नई दिल्ली, चाणक्य प्रकाशन, 1985
8. शाह, घनश्याम, मिडिल क्लास पोलिटिक्स, ए केस ऑफ एंटी-रिजर्वेशन एजीटेशन इन गुजरात, ई.पी.डब्ल्यू, वार्षिक नंबर, 1987
9. भंडारी, विजय, राजस्थान की राजनीति सामन्तवाद से जातिवाद के भंवर में, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 2007
10. शर्मा, के.एल., भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिर्वतन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006